



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2008/फाल्गुन 30, 1929

No. 94]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2008/PHALGUNA 30, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2008

जाँच शुरुआत (निर्णायक समीक्षा)

विषय : जर्मनी (ई यू) तथा कोरिया गणराज्य से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के आयातों के बारे में पाटनरोधी जाँच से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/1/2008-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने 25 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं० 14/34/2002-डी जी ए डी के तहत जर्मनी (ई यू) तथा कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित सोडियम हाइड्रो सल्फाइड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) हाइड्रोसल्फाइड के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है जिसे 1 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं० 61/2003 - सी.शु. के तहत संबद्ध वस्तु पर लगाया गया था । प्राधिकारी ने 20 अक्टूबर, 2003 को अंतिम जाँच परिणाम निकाले और 3 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना सं० 173/2003 के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. समीक्षा एवं जाँच शुरुआत हेतु अनुरोध

यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में समाप्त न किया गया हो, तो शुल्क को इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि बीत जाने पर समाप्त हो जाता है ।

परन्तु यदि समीक्षा में यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि इस प्रकार के शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकती है ।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार मै. ट्रांसपेक सिलोक्स इंडस्ट्री लि. ने ऐसी समीक्षा का अनुरोध करते हुए एक विधिवत पुष्टीकृत याचिका के साथ प्राधिकारी से संपर्क किया है। रिट याचिका सं. 2006 की 16893 (इंडियन मेटल एंड फैरो एलायज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है और ऐसी समीक्षा नियमावली के नियम 23 के अनुसार की जानी अपेक्षित है, को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात की जांच करने के लिए कि क्या लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी, अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार एतद्वारा निर्णायक समीक्षा की कार्यवाही शुरू करते हैं।

3. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद को सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के नाम से जाना जाता है, जिसे हाइड्रोसल्फाइड सांद्रण या सोडियम डाइथियोनाइट के नाम से भी जाना जाता है और इसका उत्पादन विविध विनिर्माण प्रक्रियाओं के उपयोग से किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एक रसायन है जिसका रासायनिक सूत्र एन ए 2 एस 2 ओ 4 है और यह तीक्ष्ण गंध वाला सफेद/भूरा - सफेद रबंदार पाउडर है जिसका उपयोग वस्त्र, रंजक सहायक सामग्री, न्यूनकारी एजेंट, भेषजों और बहुलकों जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसका आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28, उपशीर्ष 2831.10.10 तथा 2832.10.20 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

4. प्रक्रिया

इस जांच में इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि क्या लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को सतत रूप से जारी रखना आवश्यक है और यदि शुल्क समाप्त या परिवर्तित किया जाता है या दोनों ही स्थिति में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं है।

- (i) इस समीक्षा में दिनांक 20 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं. 14/34/2002-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे;
- (ii) शामिल देश जर्मनी (ई यू) तथा कोरिया गणराज्य है;
- (iii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2006 से 30 सितम्बर, 2007 तक (18 माह) की है।
- (iv) इस समीक्षा में उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

5. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों/उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकारों/प्रतिनिधियों भारत में उक्त उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011**

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है।

6. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

7. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अन्य हितबद्ध पार्टियों को सूचना की सार्थक समझ प्रदान करने के लिए गोपनीय सूचना के अगोपनीय रूपांतरण या उसके अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी की राय में ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसके कारण का एक विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है।

8. उपलब्ध तथ्यों का उपयोग

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2008

Initiation (Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset Review Anti-Dumping Investigations into imports of Sodium Hydrosulphite from Germany (EU) and Korea RP.

No. 15/1/2008-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) recommended provisional anti-dumping duty on import of Sodium Hydrosulphite (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Germany (EU) and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries), vide Notification No. 14/34/2002-DGAD dated 25th February 2003, which were imposed on the subject goods vide Notification No. 61/2003 Customs dated 1st April, 2003. The Authority came out with the final findings on 20th October, 2003 and definitive anti-dumping duty was imposed vide Notification No. 173/2003 dated 3rd December 2003.

2. Request for Review and Initiation

WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

In terms of the above provisions, M/s Transpek-Silox Industry Ltd has approached the Authority with a duly substantiated petition requesting for such a review. In view of the judgment of the Hon'ble Delhi High Court in the Writ Petition No 16893 of 2006 (Indian Metal & Ferro Alloys Ltd Vs Designated Authority) holding that sunset review is mandatory and such review is required to be carried out in terms of Rule 23 of the Rules, the Designated Authority hereby initiates the sunset review proceedings, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, to examine whether cessation of the duty in force would lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

3. Product under consideration

The product under consideration is known as Sodium Hydrosulphite (Also referred to as subject goods hereinafter), also known as hydrosulphite concentrate or sodium dithionite,

which can be produced using different manufacturing processes. Sodium Hydrosulphite is a chemical, with chemical formula $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$, and it is a white / greyish-white crystalline powder with pungent odour, used in such applications as textiles, bleaching aid, reducing agent, pharmaceuticals and polymers. It is imported under Chapter 28 of Customs Tariff Act, under sub-headings 2831.10.10 and 2832.10.20. The classification is, however indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

4. Procedure

The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- i. The review will cover all aspects of Notification No 14/34/2002-DGAD dated 20th October 2003.
- ii. The countries involved are Germany (EU) and Korea RP.
- iii. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st April, 2006 to 30th September, 2007 (18 months).
- iv. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

5. Submission of information

The exporters in the subject countries, their government through their Embassies/High Commissions in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

6. Time limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than forty (40) days from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

7. Submission of information on non-confidential basis

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided.

8. Use of facts available

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

9. Inspection of public file

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

R. GOPALAN, Designated Authority